भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3371

20 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

झारखंड में एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत योजनाएं

3371. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत सभी अपशिष्ट घटकों के सुरक्षित, स्वच्छ और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए झारखंड में कोई विशिष्ट योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत अब तक कितने डंप स्थलों का नवीनीकरण किया गया है और उक्त परियोजनाओं की जिला-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 को झारखंड सहित देश के शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता, अपशिष्ट के सभी अंशों का वैज्ञानिक प्रबंधन और पुराने डंपसाइटों का सुधार करने के विजन से 1 अक्टूबर, 2021 को पांच साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है।

(ख): पुराने डंपसाइट दशकों से बन गए हैं और बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। पहली बार, स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर इन डंपसाइटों को समाप्त करने का काम शुरू किया गया है। स्वच्छतम पोर्टल पर झारखंड राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सुधार के लिए कुल 38 डंपसाइट (1000 टन से अधिक कचरे के साथ) जिनमें 31 लाख मीट्रिक टन कचरा पाया गया है जो सामूहिक रूप से 141.44 एकड़ में फैले हैं इनमें से 3 डंपसाइटों का पूरी

तरह से सुधार किया जा चुका है और 16 साइटों पर पूर्ण सुधार का काम चल रहा है। कुल 1 लाख मीट्रिक टन (4%) अपशिष्ट का सुधार किया जा चुका है और 8.25 एकड़ (6%) भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया गया है। डंप साइटों का जिलेवार ब्यौरा वेबसाइट https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर उपलब्ध है।

पुराने अपशिष्ट परियोजनाओं के समय पर और पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से निपटान में सहायता करने के लिए, पुराने अपशिष्ट के निपटान के लिए दिशानिर्देश और लैंडफिल रिक्लेमेशन संबंधी परामर्शिका राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मॉडल खरीदी दस्तावेज भी तैयार किए गए हैं और बोली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी राज्यों के साथ साझा किए गए हैं।

(ग) और (घ): स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 1.0 के अंतर्गत झारखंड राज्य को 258.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत बढ़ाकर 519 करोड़ रुपये (~ 2 गुना) कर दिया गया है।इसमें से राज्य ने योजना तैयार कर ली है और 358.78 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नीति निर्देश, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और ऐड्वकसी फ्रैम्वर्क प्रदान करके स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के माध्यम से झारखंड सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

*****